Shri Morarji Desai: They are not entitled to any compensation under the new Act or ordinance

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास

{श्री सरजू पाण्डे :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की मुख्य योजनाएं क्या हैं, और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में निजी उद्योगों के विकास के लिये कितनी धन राशि दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) तथा (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

श्री भक्त दर्शन इस विवरण में जो कृत्रिम रबड़ बनाने के संयंत्र और एल्यूमीनियम बनाने के संयंत्र का जिक्र किया गया है ये कब तक कागज की फायलों में रहेंगे और कब तक वास्तव में चलाये जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह इस का बहुत बार जिक्र हो चुका है। यह मामला कागज से आगे चल चुका है और इस का प्राथमिक नक्शा तैयार हो चुका है।

वाराणसी में दियासिलाई का कारखाना

*६३९ **श्री रूप नारायण** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष वाराणसी में दियासलाई का एक कारखाना खोलने के लिये कोई राशि मंजूर की थी ;

(ख) यदि हां तो कितनी ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कारखाने के न खुलने के कारण वह राशि व्यपगत हो गई;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां थीं, और

(ङ) क्या भारत सरकार का इस काम के लिये और कुछ राशि पुन मंजूर करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में सरकारी ढंग पर दियासलाई का कारखाना खोलने की एक योजना प्रस्तुत की है।

(ख) १,१०,००० रु० का अनुदान, १,७५,७०० रु० का ऋण

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि तीलिया और डिबिया बनाने की लकड़ी किफायती दरों पर उपलब्ध नहीं होती। इसलिये औद्योगिक सरकारी ढंग पर चलने वाला दियासलाई का यह कारखाना प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेगा।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह योजना कारगर बनाई जा सकती है या नहीं।

श्री रूप नारायण क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री मनुभाई शाह यह जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव पर है न स्टेट गवर्नमेंट पर है और न सेंट्रल गवर्नमेंट पर।

श्री रूप नारायण क्या मैं जान सकता हूं कि इसके विषय में कोई प्रारम्भिक कार्रवाई की गई है कोई बोर्ड या कमेटी बनाई गई है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है ?

श्री मनुभाई शाह : सैंट्रल कोआपरेटिव ऐक्ट के नीचे जो बोर्ड हैं उस पर इसको चलाने की जिम्मेदारी है ।

Adult Civilian Training Centre

*640. **Shri Supakar:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state the progress made so far in the opening of an Adult Civilian Training Centre at Rourkela in Orissa?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): The receipt of the proposal from the State Government is awaited

Shri Supakar: May I know for how long this matter has been pending with the State Government?

Shri Abid Ali: For some months

Shri Supakar: May I know whether this proposal was started as long ago as two years?

Shri Abid Ali: Not two years, but I think it was by the end of 1955 All preliminaries have been completed, estimates have been made and the building will start during this current financial year All preliminaries have been completed but some formalities are to be gone through for which the State Government is being consulted

Shri Supakar. Is it not the duty of the Central Government to go with the construction of this project?

Shri Abid Ali: This will be done by the State Government

State Trading Corporation of India (Private) Ltd.

*641. **Pandit D. N. Tiwari:** Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state

(a) the total business done by the State Trading Corporation of India (Private) Ltd during 1956-57;

(b) the profit earned by the Corporation;

(c) the total expenditure made by the Corporation, and

(d) the capital investment made upto the 31st March, 1957?

The Minister of Commerce (Shri Kanungo): (a) Rs 43 6 crores

(b) and (c) The accounting year of the Corporation will close on the 30th June, 1957 The balance sheet will be drawn up only after that date.

(d) Rs 1 crore

Pandit D N. Tiwari: May I know whether besides internal trade this Corporation is taking up overseas trade also and, if so, in what commodities and how much foreign exchange it has earned?

Shri Kanungo: Their trade is mostly external and the lines they have been working on are iron ore, manganese ore, chrome ore, coffee, textiles, hides and skins, shoes, essential oils, edible oils, handicrafts and various other things

Pandit D. N. Tiwari: I understand that the State Trading Corporation has taken up the trade in cement and iron also May I know what organisation it has set up at provincial and district levels so that the consumers may get cement easily, because I find that there are great difficulties in consumers getting cement

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): As I have told the hon House on a number of occasions, we have not disturbed the existing trade channels for the distribution of cement They are in fact as they were in the past, excepting that the rationalised distribution now is much more efficient and much more profitable

Shri R Ramanathan Chettiar: May I know whether Government will seriously consider the question of taking in the distribution of iron and steel and the pipe materials in view of the malpractice practised by the Control Stock-holders' Association day in and day out?